

है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

क्रम सं० (i) पर निर्दिष्ट परियोजना को निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। क्रम सं० (ii) पर निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभाग द्वारा कोई अनुमोदन दिया जाना आवश्यक नहीं है। क्रम सं० (iii) पर निर्दिष्ट परियोजना, जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के दिल्ली एकक की अन्यत्र स्थापना सम्मिलित है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सहायता के लिए इस विभाग के 1998-99 के बजट में 1.00 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल की गई है। अन्यत्र स्थापना स्थल को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

प्रमुख उर्वरक संयंत्रों के समक्ष पेश आ रहा वित्तीय संकट

1049. श्री अखिलेश दास: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख उर्वरक संयंत्र वर्तमान में भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय संकट के लिये कौन-कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या देश के संयंत्रों के रख-रखाव तथा विकास योजनाओं के लिये बजट में कम प्रावधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस स्थिति से निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान उर्वरक एककों का वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों और 2 बहु राज्यीय सहकारी समितियों में से सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों को इस वर्ष के दौरान हानि हुई है।

उन उपक्रमों को हुई हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी): प्रौद्योगिकीय डिजाइन और उपकरण त्रुटिया, बारम्बार उपकरण खराबी, फीडस्टॉक बाधा, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंध समस्या, फालतू जनशक्ति और संसाधन बाधाएं।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई): उपर्युक्त के अनुसार

पाइराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एल): एस एस पी पर से निर्यात समाप्त करना और रियायत के संवितरण में विलम्ब, पाइराइट्स आधारित सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन का अंतर्निहित लागत हानि, अमझीर में पाइराइट्स खनन की प्रचालन लागत में वृद्धि, मंजूरी में गहरे भूमिगत खनन की बढ़ती हुई लागत और बढ़ी हुई परिवहन लागत।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी पी एल): सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड संयंत्रों का कम क्षमता उपयोग, रुपए के मूल्य में गिरावट डी ए पी पर रियायत में कटौती और ठेका श्रमिक समस्याएं।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम एफ एल): पुनरुद्धारित परियोजना के प्रारम्भ में विलम्ब, रुपए के मूल्य में गिरावट, फीडस्टॉक की बढ़ी हुई लागत और मिश्रित उर्वरकों पर रियायत में कटौती। हानि उठा रहे उपक्रमों के प्रचालनों को कारण बनाने हेतु किये गये प्रयासों के अलावा, उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एच एफ सी के नामरूप एकक के पुनरुद्धार हेतु स्कीम स्वीकृत कर दी गई है। इन एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने के प्रबंध भी किये गये हैं।

एच एफ सी तथा एफ सी आई के अन्य एककों के संबंध में एकक-वार व्यवहार्यता विचारों के आधार पर स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

(ii) एम एफ एल ने अपने संयंत्रों की उत्पादकता मियाद में वृद्धि करने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने तथा खपत मानकों सुधार करने हेतु अभिकल्पित अपनी महत्वपूर्ण विस्तार तथा आधुनिकीकरण परियोजना प्रारम्भ की है। पुनरुद्धारित यूरिया संयंत्र में उत्पादन सुस्थिर हो गया है जिसने वाणिज्यिक उत्पादन 01.01.1998 को शुरू किया था। शेष प्रारम्भिक समस्याएं न निराकरण हेतु प्रक्रिया लाइसेंसर को बताई गई हैं।

(iii) पी पी एल के पूंजी आधार के पुनर्गठन जो 31.3.1994 को किया गया था, के क्रम में योजना ऋणों के पुनर्भुगतान तथा 1997-98 के दौरान देयसी ब्याज को एक वर्ष के लिये आस्थगित कर दिया गया था। कंपनी ने पूंजी पुनर्गठन के माध्यम से और राहतों हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में बाधाओं पर कब्ज़ू पाने के लिये भी एक स्कीम तैयार की गई है।

(iv) पी पी सी एल ने पूंजी पुनर्गठन करने और पाइराइट्स आधारित सल्फ्यूरिक

एसिड संयंत्र को सल्फर पर आधारित संयंत्र में परिवर्तित करने हेतु स्कीमें तैयार की है ताकि इसकी आर्थिक लाभप्रदता में सुधार किया जा सके।

(v) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों को बजटीय संसाधनों की सीमा के भीतर सहायता प्रदान कर रही है ताकि ये अपनी कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं तथा अत्यावश्यक पूंजी व्यय को पूरा करने में समर्थन हो सके। गत तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता इस प्रकार है:—

(₹०/करोड़)

	1995-96	1996-97	1997-98
एच एफ सी	108.60	152.34	184.34
एफ सी आई	217.60	316.00	318.15
पी पी एल	16.00	—	15.00
पी पी सी एल	07.06	04.00	06.00
एम एफ एल	24.00	57.30	—

सरकारी उपक्रमों में उर्वरक के उत्पादन के लिये लक्ष्य

1050. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

श्री दिलीप सिंह जुदेव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक के उत्पादन में लगे सरकारी उपक्रमों में यूरिया तथा उर्वरकों की अन्य किस्मों के उत्पादन हेतु पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा वास्तविक उत्पादन कितना-कितना हुआ;

(ख) क्या उक्त वर्षों के दौरान इसके उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया उत्पादन में कमी के लिये उत्तरदायी कारकों का ब्यौर क्या है तथा सरकारी विशेषज्ञों द्वारा किये गये आकलन का पूर्ण ब्यौर क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (घ) लक्ष्यों के संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यूरिया के उत्पादन तथा अन्य उर्वरकों की समेकित सूचना संलग्न अनुपत्र में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 184 अनुपत्र संख्या 35]

नाइट्रोजन तथा फास्फेट पोषकों के रूप में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन 1997-98 के दौरान 9.4% था जो 1995-96 की अपेक्षा अधिक था। समग्र रूप से, इन उपक्रमों द्वारा यूरिया के उत्पादन में उसी अवधि के दौरान 15.3% की वृद्धि दर्ज की गयी।

Plan for Revival of Smith Street
Pharmaceuticals Limited (SSPL)

1051. SHRI DIPANKAR
MUKHERJEE: Will the Minister of
CHEMICALS AND FERTILIZERS be
pleased to refer to answers to Unstarred
Questions 2128 and 1109 given in Rajya